POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 नवम्बर 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्यों में लंबे समय से चली आ रही घटिया सामग्री, काम में लेटलतीफी और वित्तीय अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। पंचायतीराज विभाग ने जिला स्तर पर नव सृजित अधीक्षण अभियंताओं (एसई) के लिए 25 सूत्रीय जांच चार्ट तैयार किया है जो ग्रामीण विकास की गुणवत्ता को बदलने वाला साबित हो सकता है।

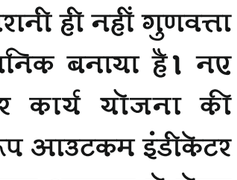
इस नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू है अधीक्षण अभियंता को सीधी शक्ति। अब पूरे जिले में एसई ही सभी निर्माण योजनाओं के नोडल अधिकारी होंगे। वे जिले के किसी भी ब्लॉक में बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वे अपनी तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट बिना किसी स्थानीय दबाव के सीधे जिला कलेक्टर को भेजेंगे। इसकी प्रतिलिपि जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भी जाएगी।

इससे पहले रिपोर्ट कई स्तरों पर अटक जाती थी, अब जवाबदेही सीधे तय होगी। सरकार ने केवल निगरानी ही नहीं गुणवत्ता नियंत्रण को भी वैज्ञानिक बनाया है। नए निर्देशों के अनुसार कार्य योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप आउटकम इंडीकेटर तय होंगे। मॉडल लागत अनुमान से लेकर लैब परीक्षण तक के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।

लैब कैलिब्रेशन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का नियमित निरीक्षण, टीम टेस्टिंग और वहां मौजूद उपकरणों का अधिकृत संस्थाओं से नियमित कैलिब्रेशन अनिवार्य होगा। यदि घटिया निर्माण या ड्राइंग-डिजाइन में विचलन पाया गया, तो कार्यकारी संस्था को तत्काल निर्देश देकर नियमानुसार कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अगले वित्तीय वर्ष से बैंकिंग नियमों में होगा बड़ा बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए आरबीआई कई अहम बैंकिंग नियमों की समीक्षा कर रहा है। अब तक 40 से ज्यादा मसौदे तैयार किए जा चुके हैं। इनमें 500 से ज्यादा प्रक्रियाओं, कामकाज के तौर तरीकों और नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है। नए नियम 1 अप्रेल 2027 से लागू होंगे। इनमें सबसे प्रमुख है लोन की प्रक्रिया का सख्त होना है। अगले साल से बैंक केवल आपको मौजूदा कमाई नहीं, बल्कि भविष्य की जोखिमों को देख कर लोन मंजूर करेंगे।



नए नियमों के लिए आरबीआई पिछले एक साल से समीक्षा कर रहा है। इसने बैंकों से जुड़े 9446 पुराने व बेकार हो चुके नियम, दिशा निर्देश, नोटिफिकेशन को हटाया या इन्हें वापस लिया है। इसी आधार पर बैंकिंग व्यवस्था के कई नियमों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इन बदलावों में केवल 4 बिंदुओं पर फोकस है। कर्ज की मंजूरी, ब्याज दर, बैंक में जमा रकम और कर्ज वसूली। नए मसौदों में ब्याज की गणना को अधिक स्पष्ट बनाने और सामान्य तौर पर मासिक आधार पर ब्याज लेने का प्रस्ताव है। ब्याज दरों में पूरी पारदर्शिता होगी। बैंक ब्याज दर किस आधार पर बढ़ा या घटा रहा है, यह समझना आसान होगा। 10 नए नियम हमारी जिंदगी पर सीधे असर डालेंगे। इनमें बैंकों से कर्ज लेना कुछ मुश्किल हो सकता है। रिस्क पर सीधे बोर्ड डायरेक्टर्स नजर रखेंगे। बसूली एजेंट यदि कोई बदतमीजी करे तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा।

ब्रांडेड घड़ी वापस नहीं लौटाना कंपनी व विक्रेता को पड़ा भारी



जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने दोषयुक्त ब्रांडेड घड़ी बेचने और मरम्मत के लिए देने के बाद वापस नही लौटाने के मामले में विक्रेता और निर्माता कंपनी का सेवा दोष मानते हुए उपभोक्ता नीम क ा थाना, सीकर निवासी राहुल वशिष्ठ के पक्ष में फैसला दिया है। मामले के अनुसार राहुल वशिष्ठ ने 21 मार्च 2024 में 1,50,790 रुपए में ब्रांडेड घड़ी खरीदी थी। निर्माण संबंधी दोष होने के कारण घड़ी में बार-बार समस्याएं आने लगी। इसे ठीक करने के लिए कई बार विक्रेता को दिया गया। परिवादी ने अंतिम बार 11 मार्च 2026 को घड़ी मरम्मत के लिए दी, लेकिन इसके बाद विपक्षीगण ने घड़ी वापस नहीं लौटाई।

मामले में नोटिस तामील हाने के बावजूद घड़ी निर्माता और विक्रेता की ओर से उपभोक्ता आयोग में कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए विपक्षीगण को आदेश दिया कि परिवादी राहुल वशिष्ठ को उसी मॉडल की घड़ी दी जाए, या घड़ी की कीमत 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित लौटाई जाए। साथ ही आयोग ने परिवादी को 30 हजार रुपए हर्जाने स्वरूप देने के निर्देश भी दिए हैं।

झालावाड़ अस्पताल में फर्जीवाड़ा

अस्पताल में मरीज भर्ती हो गए, उनका इलाज भी हुआ और डिस्चार्ज भी, लेकिन यह सब हुआ केवल कागजों में। जिले के सबसे बड़े सरकारी एसआरजी अस्पताल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से करीब 60 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया गया।

बीमा कंपनी ने 82 मामलों की अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड से जांच कराई तो तीन चार मामलों को छोड़कर अधिकांश आईपीडी और डिस्चार्ज टिकट फर्जी पाए गए। यह फर्जीवाड़ा मेडिकल कॉलेज एवं एसआरजी अस्पताल की तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट से सामने आया। मामले की जांच रिपोर्ट अस्पताल के अधीक्षक को सौंप दी गई है।

बारिश बरसी पर धरती तरसी...

शहरों के पास बारिश की बूंदों को संभालने की जगह घट रही है। धरती का स्पंज सिकुड़ रहा है, यानी खुली भूमि घट रही है और पक्की जमीन (कंक्रीट के जंगल) बढ़ रही है। नतीजा, भूजल के स्तर में गिरावट आ रही है और जमीन के ऊपर बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। शहरों का विस्तार प्राकृतिक 'स्पंज' को भी छोटा कर रहा है, जो बारिश के पानी को सोखता था।



चिंताजनक यह है कि डब्ल्यूआरआइ की 10 भारतीय शहरों की रिपोर्ट बताती है कि पक्के निर्माण का 44% हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में हुआ, जहां भूजल रिचार्ज की क्षमता ज्यादा थी। यानी अब वहां सड़कें, इमारतें और कंक्रीट की चादर है। इससे इन शहरों में रोज करीब 87 करोड़ लीटर पानी का जमीन में जाने का रास्ता बंद हो गया है।

44 लाख घरों को नल का इंतजार

हर ग्रामीण परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन (जेजेएम) राजस्थान में सुस्त रफ्तार से जूझ रहा है। प्रदेश के एक 1 करोड़ 7 लाख 87 हजार 724 ग्रामीण परिवारों में से अब तक 63 लाख 90 हजार 739 घरों (59.24%) तक ही नल कनेक्शन पहुंच सके हैं।

करीब 44 लाख परिवार अब भी नल कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। मिशन की समय सीमा 2028 तक बढ़ाए जाने के बावजूद काम अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है। दूसरी ओर, संवेदकों के करीब 3200 करोड़ रुपए का भुगतान दो साल से लंबित होने के कारण प्रदेश में 90% पेयजल परियोजनाओं का काम ठप बताया जा रहा है।

निगरानी सिस्टम होगा मजबूत

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री, तय समय सीमा की अनदेखी और वित्तीय अनुशासनहीनता पर अब प्रशासनिक व तकनीकी लगाम कसने की तैयारी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला स्तर पर नवसृजित अधीक्षण अभियंताओं का 25 सूत्रीय जॉब चार्ट तैयार किया है।

इस प्रशासनिक ढांचे का सबसे अहम पहलू यह है कि अब अधीक्षण अभियंता किसी स्थानीय दबाव में आए बिना तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट सीधे जिला कलेक्टर को भेजेंगे। इसकी प्रतिलिपि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता को जाएगी। जॉब चार्ट में गुणवत्ता नियंत्रण को सर्वोपरि रखा गया है।

चिट्ठियों से आगे बढ़ा डाकघर

बदलते समय के साथ अब डाकघर की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। कभी चिट्ठियों और मनिआर्डर तक सीमित रहने वाली डाक सेवाएं अब बैंकिंग, आधार और लाजिस्टिक्स जैसी सुविधाओं के जरिए आमजन की जरूरतों से जुड़ रही हैं। डाकघर सेवाएं अब ट्रैकिंग और ई-कामर्स तक पहुंची है।

राजस्थान परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल सुशील कुमार ने बताया कि विभाग का लक्ष्य तकनीक और व्यापक नेटवर्क के जरिए सरल, सुलभ, विश्वसनीय और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस वर्ष डाक सप्ताह की थीम एक डाक नेटवर्क असीम संभावनाएं रखी गई है। सेवाओं के जरिए आम लोगों की भागदौड़ कम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब गांव से सीधे विदेश तक डाक पहुंचेगी।

लखपति दीदी योजना से बढ़ी आय

आइआइएम अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक लखपति दीदी योजना से महिलाओं की आय और बचत में बड़ा सुधार हुआ है। लखपति दीदी परिवारों की औसत मासिक आय 61% बढ़ी, जबकि बचत 61.7% बढ़ी है। पिछले एक साल में महिला उद्यम 48% बढ़े।

यह स्टडी नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक के बीच 17 राज्यों के 6500 लोगों पर की गई। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने कहा कि यह परिणाम उत्साहजनक है। यह योजना 2023 में शुरू हुई थी जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सालाना आय 1 लाख से अधिक बनाना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी बनाकर ग्रामीण गरीब परिवारों को सशक्त बनाना है।

छापरवाड़ा बांध को विश्व धरोहर सम्मान

जयपुर जिले स्थित दूदू क्षेत्र के करीब 132 वर्ष पुराने ऐतिहासिक छापरवाड़ा बांध को फ्रांस में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का विश्व धरोहर सिंचाई सम्मान प्रदान किया गया है। वर्ष 1894 में सिंचाई के लिए निर्मित यह बांध आज भी हजारों किसानों के खेतों की प्यास बुझाने का माध्यम बना हुआ है।

इस सम्मान के लिए उन सिंचाई संरचनाओं का चयन किया जाता है, जिन्होंने लम्बे समय तक कृषि, जल प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध की पाल करीब 4.2 किमी है और यह 52 गांवों की 50 हजार बीघा जमीन को सींच रहा है। संरचना, विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र और वैज्ञानिक तरीके से बने नहर तंत्र इसे खास बनाते हैं।

इनोवेशन में प्रदेश का बड़ा योगदान

जयपुर में आयोजित राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के इनोवेशन इकोसिस्टम में राजस्थान का योगदान अहम है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय काम किया है। उन्होंने स्टार्टअप सेवाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में स्टार्टअप में निवेश चार गुना बढ़कर 1054 करोड़ रुपए हो गया है। इससे रोजगार के अवसर दोगुने से अधिक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि ढाई साल में राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत 4828 नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं।

दुनिया के लिए केस स्टडी बना गांव

राजसमंद जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा पीपलान्त्री गांव देश ही नहीं दुनिया के लिए एक निर्मल, स्वजल, आदर्श और अब केस स्टडी ग्राम भी बन गया है।



इस गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा का बीड़ा भी गांव वाले ही मिलकर उठाते हैं। दीमक आदि से बचाव के लिए वे पेड़ों के चारों ओर एलोवेरा के पौधे भी लगाते हैं। गांव में पिछले सालों में सवा लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं।

इसके अलावा गांव के निवासी मिलकर 21 हजार रुपए व बिटिया के माता-पिता 10 हजार रुपए कुल 31 हजार रुपए की बैंक में 20 साल के लिए बिटिया नाम के एफ.डी.भी करवाते हैं। बिटिया के माता-पिता लिखित में हलफनामा भी देते हैं कि वे अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलवाएंगे और कानूनी उम्र होने पर ही उसका विवाह करेंगे। गांव में लगाए गए पेड़ और एलोवेरा के पौधे गांव के निवासियों के लिए जीविका का साधन बन गए हैं। इस अनूठी परम्परा की शुरुआत गांव के पूर्व नेता श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा उनकी लड़की के निधन पर उसके सम्मान में आरंभ की गई थी। आज देश-विदेश के गांवों के लिए यह मिसाल प्रेरणा दायक बन रही है।

बढ़ रहा है महिला समूह का कारोबार

गांवों में जिन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित मान लिया गया था वे आज करोड़ों रुपए के टर्नओवर का कारोबार संभाल कर मिसाल बन रही हैं। करीब पांच साल पहले कोटा के रामगंज मंडी से 10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने मिलकर तेल बनाने की छोटी सी शुरुआत की थी।

आज यह बिजनेस कोटा और बारां जिले में 452 गांवों तक फैला चुका है। इसमें अब 18 हजार 350 महिलाएं जुड़ी हुई है और सालाना टर्न ओवर 45 करोड़ रुपए से अधिक का है। ये अब रीको इंडस्ट्रियल एरिया में खुद की मिल में हाड़ौती ब्रांड का सरसों का तेल बाजार में बेच रही है। अब ये महिलाएं मसाला बिजनेस में भी उतरने की तैयारी कर रही है। खासियत यह है कि कंपनी के संचालन का पूरा काम महिलाएं ही देख रही हैं।

ग्रामीण महिलाएं संभाल रही उद्यम

गांव में लोगों को उद्यम से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) शुरू किया था। इसके तहत देश में केरल में सर्वाधिक 62,166 उद्यम शुरू हुए । जबकि पूरे देश में 4.32 लाख से ज्यादा उद्यम शुरू हुए। देशभर में ग्रामीण स्टार्टअप की सफलता के क्षेत्र में केरल सबसे आगे है।

यहां 10 साल में 62 हजार से ज्यादा उद्यम शुरू हुए। कल्लीपुर की किस्टल बाई कपड़े के बैग सिलती थी पर उनके पास ज्यादा खरीददार नहीं थे। तब उसने कुदुंबश्री से सम्पर्क किया। उन्होंने चैतन्य क्लाथ बैग नाम से उद्यम शुरू किया। उसे एसवीईपी के तहत मदद मिली। अब वह महीने में 3-4 लाख रुपए तक कमा रही है। इन उधमों से अब 84,538 लोग जुड़े हैं और सब हर महीने 10 हजार रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। खास यह है कि इन उद्यमों मे 90 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कटूर', जयपुर